भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3473

17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

फेम-दो योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

3473. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेम-दो योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में ईवी अपनाए जाने का संवर्धन करने में इन प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया हैं; और
(ग) यदि हां, तो ऐसे आकलन के क्या निष्कर्ष रहे?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): फेम-II स्कीम 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2024 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई थी। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। इसके बजाय, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कमी के रूप में उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को प्रोत्साहन/रियायतें प्रदान की गईं, जिससे व्यापक रूप से अपनाने में सुविधा हुई। इन प्रोत्साहनों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम, अर्थात् ईवी विनिर्माताओं) को की गई थी।

(ख) और (ग): सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है, जिसमें मांग और आपूर्ति-पक्ष प्रोत्साहन/सब्सिडी, कर छूट और ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 9.68 गुना वृद्धि हुई है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

इसके अलावा, फेम-II स्कीम के लाभ को बनाए रखने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 सितंबर 2024 को पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को अधिसूचित किया। यह 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दो साल की स्कीम है। ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-बस और ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के अलावा, यह स्कीम ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस और वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन का भी समर्थन करती है।

******